for the IIIrd National Games scheduled to be held this year in Maharashtra; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SOPRTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKUL WASNIK): (a) Yes, Sir.

(b) The assistance will be provided for creation of infrastructure facilities in accordance with the pattern laid down in Scheme for grants for creation of sports infrastructure. Central assistance to the extent of Rs. 124 lakhs has so far been granted for the State level Sports Complex at Pune. This facility will be used for the national games. In respect of other proposals Govt. of Maharashtra has been asked for further details.

In addition a sum of Rs. 45 lakhs has been released in the current year for laying synthetic track at Pune.

Public/Private Sector to Promote Sports Activity

1423. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the setting up of a hockey academy by Steel Authority of India Limited in an effort of revise the game;

(b) if so, whether Sports Authority of India would also be associated in the venture; and

(c) whether Government propose to encourage other big public|private sector units to promote atleast one game each so as to enable the country to reach international standards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (SHRI MUKUL WASNIK): (a) Yes, Sir.

(b) Sports Authority of India has been associated with the venture by way of providing technical guidance for setting up of the Academy.

(c) It is proposed to involve other big public|private sector units in the promotion of sports.

तकनीकी शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए विश्व बैंक से सहायता

1424. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने दिल्ली और अन्य कई राज्यों को तकनीकी शिक्षा के विकास और विस्तार हेतु बड़ी मात्रा में सहायता राशि देने की घोषणा की है, यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त सहायता राशि का इस्तेमाल कब से शुरू हो जाएगा और इस सहायता राशि से शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यह धनराशि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को ही उपलब्ध कराई जा रही है, न कि सभी राज्यों को, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और हरियाणा को दी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) विश्व बैंक 16 राज्यों और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निकों को शामिल करते हुए, तकनीशियन (पालिटेक्निक) शिक्षा के आधुनीकीकरण और उत्थान के लिए दो परियोजनाओं के अंतर्गत 1990–99 की अवधि के लिए विशेष आहरण अधिकारों (एस०डी०आर०) 373.7 मिलियन (अमरीकी डालर लगभग 517 मिलियन के समकक्ष) फिकी ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है । पहली परियोजना 5–12–1990 को संचालित की गई और दूसरी 29–1–1992 को संचालित की गई । परियोजनाओं में, विद्यमान राज्यों में संबंधित कार्यकलापों के लिए अथवा पहले शामिल न किए गए अतिरिक्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अंतर्निमित लचीलापन है । तदनुसार, संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी को हाल ही में शामिल किया गया है और परियोजनाओं में गोवा राज्य को शामिल किए जाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए गए हैं । प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को बैंक-सहायता की राशि अनुमोदित परियोजना कार्यकलापों पर किए गए वास्तविक खर्चे तथा विश्व-बैंक से दावा की गई प्रतिपूर्ति पर निर्भर करती है । प्रत्येक राज्य (हरियाणा सहित) संघ शासित क्षेत्र के परियोजना–प्रस्ताव की अनुमानित लागत, जैसी विश्व-बैंक द्वारा अनुमोदित की गई है, विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए) । परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में आरम्भ की गई योजनाओं के ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं ।

विवरण I

तकनीकी शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए विश्व-बैंक से सहायता के संबंध में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के परियोजना प्रस्ताव की अनुमानित लागत :

(रुपए करोड़ों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कुल अनुमानित परियोजना लागत
	परियोजना–I	
1.	बिहार	88
2.	गुजरात	65
3.	कर्नाटक	53
4.	केरल	34
5.	मध्य प्रदेश	100
6.	उड़ीसा	57
7.	राजस्थान	45
8.	उत्तर प्रदेश	200
	परियोजना–II	
1.	आन्ध्र प्रदेश	80
2.	असम	30
3.	हरियाणा	81
4.	हिमाचल प्रदेश	20
5.	महाराष्ट्र	123
6.	पंजाब	79
7.	तमिलनाडु	68
8.	पश्चिम बंगाल	86
9.	संघ/शासित क्षेत्र दिल्ली	24
10.	संघ शासित क्षेत्र पांण्डिचेरी	14

विवरण–II

तकनीकी शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए विश्व-बैंक से सहायता के सम्बन्ध में परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा आरम्भ की गई योजनायें

विस्तार क्षमता

1. विद्यमान पालिटेक्निकों में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में नए कार्यक्रमों

को आरम्भ करना ।

2. नए पालिटेक्निकों को सीमित संख्या में आरम्भ करना ।

3. स्थापित किए गए पालिटेक्निकों को सुदृढ बनाना ।

4. सतत शिक्षा केंद्रों और खेलों को स्थापित करना ।

5. ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों की महिलाओं, छात्रों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कार्यक्रम का विस्तार करना ।

6. अतिरिक्त भवनों, छात्रों के छात्रावासों और स्टाफ-निवासों का निर्माण ।

कोटि-सुधार

1. पालिटेक्निक शिक्षकों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम ।

2. राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या विकास केंद्रों और अध्ययन स्रोत विकास केंद्रों की स्थापना करना ।

3. संगणक केंद्रों की स्थापना करना ।

4. प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आधुनिक बनाना ।

5. यमुना बिन्दु प्रवेश और ऋण-पद्धति को आरम्भ करना ।

6. उद्योग-संस्था-आपसी-तालमेल केंद्रों सैलों को स्थापित करना ।

दक्षता सुधार

1. राज्य निदेशालयों और तकनीकी शिक्षा बोर्डों की प्रशासनिक और प्रबंध-संरचना को सुदृढ बनाना ।

2. राज्य और पालिटेक्निकल स्तरों पर परियोजना-क्रियान्वयन इकाइयों की स्थापना करना ।

3. चुनिन्दा पालिटेक्निकों को स्वायत्तता स्वीकृत करना ।

4. अनुरक्षण कार्यक्रमों की स्थापना करना और आन्तरिक राजस्व उत्पति मे सुधार करना ।

Urdu Medium Composite Model School in Delhi

1425. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of composite model schools established so far in Delhi;

(b) the number of Urdu medium composite model schools established so far; and

(c) whether the students of Urdu medium composite model schools are getting education through the same medium in the primary schools, if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (c): According to the information furnished by Delhi Administration, 1991 Government composite model schools are es tablished by the Education Department of Delhi Administration, out of which 3 are Urdu medium composite model schools. In other composite schools the provision of teaching Urdu as a subject is made according to the requirements.

मुरादाबाद में विद्यालय की छत का गिर जाना

1426. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 1993 को दिल्ली से प्रका-